भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2632
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाना है)

देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

2632. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद की वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित आर्थिक वृद्धि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्रीय सहयोग के लिए अपनी विकास क्षमता का लाभ उठाते हुए भारत को वैश्विक आर्थिक मंचों पर अग्रणी बनाने के लिए क्या रणनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) महेसाणा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन में सरकार द्वारा वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाओं के द्वारा पड़े दीर्घकालिक प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लचीलापन दिखाने वाले सेवा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार वैश्विक प्रतिकूलताओं को कम करने और आगामी तिमाहियों में भारत के आर्थिक विकास को सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम उठा रही है या अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) केंद्रीय बजट 2025-26 में 2025-26 के लिए 10.1 प्रतिशत की मामूली जीडीपी वृद्धि की परिकल्पना की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.3 और 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। सरकार ने 2025-26 के लिए विकास के किसी भी क्षेत्र-वार अनुमान को प्रकाशित नहीं किया है।

(ख) सरकार, विभिन्न वैश्विक आर्थिक मंचों में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी वैश्विक आर्थिक विकास की हिमायत करती रही है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, भारत वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और विकास की जरूरतों को भी व्यक्त करता रहा है। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता संबंधी लाभ को आगे बढ़ाने, क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर रोडमैप, नए शहरों का वित्तपोषण, कर पारदर्शिता संवर्धन और जलवायु वित्त जुटाने और सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त को सक्षम करने की दिशा में भारतीय जी20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहलों ने वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है।

(ग) सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाएं भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी, नौकरी के अवसरों और बाजार पहुंच को बढ़ाती हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और विकास में क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं। महेसाणा में रेलवे, सड़क, जल आपूर्ति और सिंचाई जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का भी इसी तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में सेवा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया गया है। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रस्तावित पहल, कौशल विकास, निजी क्षेत्र के नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र, उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने और गिग श्रमिकों को सहायता देने राज्यों के लिए मार्गदर्शन के रूप में राष्ट्रीय फ्रेमवर्क शामिल हैं। वाणिज्यिक सेवाओं को अवसंरचना की अड़चनों, लॉजिस्टिक लागत और विनियामक अनुपालनों में ढील में उत्तरोत्तर कमी से लाभ होता है। सरकार के व्यापार सुविधा संबंधी उपाय, निर्यात प्रोत्साहन, डिजिटल व्यापार प्लेटफार्मों की शुरूआत, व्यापार समझौते, निर्यात हब पहल के रूप में जिले, व्यापार प्रतिस्पर्धा और बाजार पहुंच में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई लॉजिस्टिक्स एकीकरण और विदेश व्यापार नीति से निर्यात और संबंधित सेवाओं में मजबूती आने की उम्मीद है।

(ङ) वैश्विक बाधाओं के बीच, मजबूत पूंजीगत व्यय, अवसंरचना के निर्माण, शहरी विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास और कृषि समुत्थानशीलता पर सरकार के निरंतर बल से आगामी तिमाहियों में आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। बजट 2025-26 में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को उनमें से प्रत्येक के तहत विभिन्न उपायों के साथ विकास इंजन के रूप में पेश करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय कार्यसूची प्रस्तावित की गई है।

****